CUTS International

PRESS RELEASE

CONSUMER UNITY & TRUST SOCIETY - A registered, recognised, non-partisan, non-profit and non-government organisation pursuing social justice and economic equity within and across borders

''राजस्थान का 2022–23 का बजट किसान हितेषी'', 'कट्स' इन्टरनेशनल

जयपुर, 24 फरवरी, 2022

'कट्स' ने राजस्थान सरकार द्वारा अलग से प्रस्तुत कृषि बजट को किसानें के हित में बताया है। इस बजट में मुख्य रूप से प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ाने के लिए विशेष राशि प्रस्तावित की गई है, इससे प्रदेश के किसान जैविक खेती की ओर अग्रसर होंगे।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) राजस्थान में पिछले कई वर्षों से जैविक खेती बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में कार्य कर रही हैं। राज्य में किसानों को जैविक खेती से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किया जा रहा है। संस्था का मानना है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि बजट से राज्य जैविक खेती के क्षेत्र में 600 करोड़ के प्रावधान के तहत राजस्थान जैविक खेती मिशन एवं ओर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है, इससे जैविक खेती करने वाले किसानों की प्रमुख समस्या यथा आदान की कमी, बाजार की उपलब्धता, बेहतर तकनीक आदि का समाधान हो सकेगा। इसके अलावा प्रदेश में घरेलू अनाज यथा बाजरा, ज्वार आदि को प्रोत्साहित करने के लिए मिलेट प्रमोशन मिशन की स्थापना के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है जो कि प्रशंसनीय है।

जैविक खेती के अलावा बगीचों की स्थापना के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना, सभी जिलों में सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता दिन में करवाना, मधुमक्खी पालन एवं मोटे अनाज के लिए उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित करना, दूध पर मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाना, तारबंदी योजना में संशोधन करना आदि ऐसे निर्णय हैं जिससे प्रदेश के किसान को सभी योजनाओं का लाभ सरलता से मिलेगा।

इसके अलावा, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें और उदारता की जरूरत हैं, जैसे वर्ष 2016 में घोषित जैविक डूंगरपुर योजना पर अमल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पशुपालक किसानों के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चरणबद्ध योजना प्रस्तावित की जानी चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:
राजदीप पारीक (94616 70755)/धर्मेन्द्र चतुर्वेदी (94142 02868)
'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग
डी– 218, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर– 302 016, भारत
दूरभाष: 91–.5133259, 2282821/2282482 फैक्स: 91–141–4015395
ईमेल: rdp@cuts.org ; dc@cuts.org
वेबसाइट: http:/www.cuts-international.org

CUTS International

PRESS RELEASE

''राजस्थान का 2022-23 का बजट किसान हितेषी'', 'कट्स' इन्टरनेषनल

जयपुर, 24 फरवरी, 2022

'कट्स' ने राजस्थान सरकार द्वारा अलग से प्रस्तुत कृषि बजट को किसानें के हित में बताया है। इस बजट में मुख्य रूप से प्रदेष में जैविक खेती को बढ़ाने के लिए विषेष राषि प्रस्तावित की गई है, इससे प्रदेष के किसान जैविक खेती की ओर अग्रसर होंगे।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) राजस्थान में पिछले कई वर्षों से जैविक खेती बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में कार्य कर रही हैं। राज्य में किसानों को जैविक खेती से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किया जा रहा है। संस्था का मानना है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि बजट से राज्य जैविक खेती के क्षेत्र में 600 करोड़ के प्रावधान के तहत राजस्थान जैविक खेती मिषन एवं ओर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है, इससे जैविक खेती करने वाले किसानों की प्रमुख समस्या यथा आदान की कमी, बाजार की उपलब्धता, बेहतर तकनीक आदि का समाधान हो सकेगा। इसके अलावा प्रदेष में घरेलू अनाज यथा बाजरा, ज्वार आदि को प्रोत्साहित करने के लिए मिलेट प्रमोषन मिषन की स्थापना के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है जो कि प्रषंसनीय है।

जैविक खेती के अलावा बगीचों की स्थापना के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर 75 प्रतिषत करना, सभी जिलों में सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता दिन में करवाना, मधुमक्खी पालन एवं मोटे अनाज के लिए उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित करना, दूध पर मिलने वाली अनुदान राषि को बढ़ाना, तारबंदी योजना में संषोधन करना आदि ऐसे निर्णय हैं जिससे प्रदेष के किसान को सभी योजनाओं का लाभ सरलता से मिलेगा।

इसके अलावा, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें और उदारता की जरूरत हैं, जैसे वर्ष 2016 में घोषित जैविक डूंगरपुर योजना पर अमल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पषुपालक किसानों के लिए चारे की उपलब्धता सुनिष्चित करने हेतु चरणबद्ध योजना प्रस्तावित की जानी चाहिए।